चंद्र देव सिंह

बनाम

प्रोकाश चंद्र बोस एवं अन्य

(एस.जे. इमाम, के. सुब्बाराव, एन. रघुवर दयाल, जे.आर. मुधोलकर, जेजे.)

आपराधिक कानून-कार्यवाही अन्तर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता- प्रतिवादी संख्या 1 और अन्य द्वारा- पुनर्विचार याचिका व्यक्ति-क्या प्रतिवादी नंबर 1 के पास प्रक्रिया जारी होने से पहले दाण्डिक प्रकरण में सुनवाई का अधिकार है- प्रक्रियात्मक दोष- कमिटल कार्यवाही में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और साक्ष्यों पर विचार-कारणों का अंकन- आपराधिक संहिता प्रक्रिया, 1898 (1898 का अधिनियम 5), धारा 202 ,203

एक प्रथम सूचना रिपोर्ट यह कहते हुए दर्ज की गई थी कि प्रतिवादी नंबर 1 और कुछ अन्य ने हत्या की। तत्पश्चात मृतक का रिश्तेदार होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर मिथ्या आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई और आक्षेप किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति भी थे जिन्होंने हत्या की थी तथा प्रार्थना की गई कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध तामील जारी की जाए। जिस सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष यह शिकायत की गयी थी, उनके द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को जांच करने और एक रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद मृतक के भतीजे ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है प्रतिवादी नंबर 1 ने हत्या की थी। उपखण्ड अधिकारी ने प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी को निर्देशित किया इस शिकायत की भी जांच कर रिपोर्ट दें। दौराने जाॅच शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए गवाह के अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति दी गई थी और और दो व्यक्तियों तथा प्रतिवादी संख्या 1 से अदालती गवाहों के रूप में पूछताछ की गई। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने धारा 203 अपराधी प्रक्रिया संहिता,

1898 के तहत जांच करते हुये, एक रिपोर्ट बनाई जिसमें कहा गया कि पहली शिकायत में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। उन्होंने दूसरी शिकायत पर एक और रिपोर्ट बनाई जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं था। उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने पहली शिकायत में उल्लेखित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता द्वारा दूसरी शिकायत में दायर पुनरीक्षण आवेदन पर सत्र न्यायाधीश ने उप-खण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया लेने वाले प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ अग्रिम जांच करें जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा मामले को उच्च न्यायालय में निगरानी में ले जाया गया । दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई और प्रतिवादी नंबर 1 और तीन अन्य में से एक को अनुमति दी गई थी। वर्तमान अपील भारत के संविधान की धारा 134 (1) (सी) के तहत दिए गए प्रमाण पत्र के तहत है।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के मुख्य तर्क थे (1) प्रतिवादी नंबर 1 के पास उपस्थित होने का और प्रक्रिया जारी होने से पहले आपराधिक मामला में लड़ने का कोई अधिकार नहीं था (2) उच्च न्यायालय द्वारा तामील जारी करने के प्रश्न के निर्धारण के लिए लागू किया गया परीक्षण गलत था (3) मजिस्ट्रेट को धारा 202 दप्रसं के तहत साक्ष्य का विवेचन विचारण की तरह करने का अधिकार नहीं था (4) उप. खण्ड मजिस्ट्रेट को धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए शिकायत ख़ारिज करते समय कारण देना चाहिये था।

अभिनिर्धारित किया कि प्रक्रिया जारी होने तक बिल्कुल भी एक आरोपी व्यक्ति तस्वीर में नहीं आता है। भले ही उसको वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी गई है, परन्तु कार्यवाही में भाग लेने देने और न ही मजिस्ट्रेट को उसे ऐसा करने की अनुमति देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है उसके कहने पर सवाल नहीं पूछ सकता और न ही वह

किसी गवाह की जांच कर सकता है उस व्यक्ति के कहने पर। इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच दूषित हो गई।

वाडीलाल पांचाल बनाम दत्तात्र्य दुलाजी घाडिगसोनाकर, [1961] 1 एससीआर 1, संदर्भित।

इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि क्या प्रक्रिया जारी की जानी है लागू होने वाला परीक्षण यह है कि "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं" ना कि क्या दोषसिद्धि का पर्याप्त आधार है या नहीं।

परमंद ब्रह्मचारी बनाम एम्परर, एआईआर 1930 पैट 30 राधा किशुन साव बनाम एस.के. मिश्रा, ए.आई.आर. 1949 पैट. 36, रामकिस्तो साहू बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1952 पैट. 125, सम्राट बनाम जे.ए. फिनान, ए.आई.आर. 1931 बम. 524 एवं बैद्यनाथ सिंह बनाम मसप्रैट, (1886) आई.एल.आर 14 कैल. 141 पर चर्चा की गई।

धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान दर्ज किए गए बयानों पर या दूसरी शिकायत में पेश किये गये साक्ष्य विचार करने के का अधिकार नहीं है। जो मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय भी वैसा करने में अक्षम था।

जहां प्रथम दृष्टया मामला को वहां दोनों पक्षों की ओर से कहने के लिये बहुत कुछ हो परन्तु एक प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट अभियुक्त को मुकदमे का विचारण करने के लिए बाध्य है।

रामगोपाल गणपतराय रुइया बनाम बॉम्बे राज्य, [1958] एससीआर 618, संदर्भित।

जब कोई मजिस्ट्रेट मुकदमे का विचारण करने के पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण किसी शिकायत को खारिज कर देता है तो ऐसा करने के उसके कारणों को रिकार्ड करना आवश्यक है।

विली (विलियम्स) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [1955] 2 एस.सी.आर 1140, माना गया।

एक व्यक्ति के खिलाफ जांच करने से नहीं रोका जा सकता यदि उसी अपराध के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध जांच लंबित हो।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 155/1960।

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 620 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 27 जनवरी, 1960 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता की ओर से सुकुमार घोष।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए जय गोपाल सेठी, सीएलसरीन और वाई. कुमार।

22 जनवरी, 1963 न्यायालय का निर्णय मुधोलकर, जे. द्वारा सुनाया गया था।

यह भारत के संविधान की धारा 134 (1) (सी) के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र की अपील है। इस अपील के प्रयोजन के लिए जो तथ्य प्रासंगिक हैं वे संक्षेप में ये हैं:

25 दिसंबर, 1957 को दोपहर 1 बजे पंचानन राय नामक व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 पीएम पर पुलिस स्टेशन, 24 परगना जिले भांगोर में दर्ज करायी जिसमें आरोप है कि प्रतिवादी नंबर 1 (प्रोकाश चंद्र बोस) जो एक मत्स्य पालन का मालिक है, ने नागेश्वर सिंह नाम के एक व्यक्ति की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो मुखबिर के मालिक के मत्स्य पालन में तैनात एक दरवान था। घटना के बाद,

हमलावरों के दल का पीछा किया गया, लेकिन मुख्य अपराधी अर्थात् प्रतिवादी नंबर 1 अपनी कार में भागने में सफल रहा। उसके दो सहयोगियों पन्नालाल साहा और शंकर घोष को स्थानीय लोगों ने गिरफ्तार कर थाने में पेश किया. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने जांच की, लेकिन अंततः उन्होंने 17 सितंबर, 1958 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3 नवंबर, 1958 को एक महेंद्र सिंह, जिसने मृतक दरवान का दूर का रिश्तेदार होने का दावा किया था, लेकिन मृतक की विधवा ने इस तथ्य से इनकार किया है - पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ 24 परगना अलीपुर के उप-खण्ड मजिस्ट्रेट श्री सीएल चौधरी के समक्ष शिकायत दर्ज की और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए कहा। आरोप है कि उन लोगों ने नागेश्वर सिंह की हत्या कर दी है। शिकायत में इस आशय का एक बयान भी शामिल था कि 25 दिसंबर, 1957 को पंचानन रॉय द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई पहली सूचना रिपोर्ट झूठी थी और उन्होंने ऐसा अपने मास्टर बिधु भूषण सरकार के कहने पर किया था, जो प्रतिवादी के दुश्मन थे। नंबर 1. महेंद्र सिंह की शपथ पर जांच करने और पुलिस कागजात को देखने के बाद, विद्वान उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने श्री एनएम चौधरी, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, को महेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच करने और एक एक निश्चित तिथि तक उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

महेंद्र सिंह की शिकायत की जांच के लंबित रहने के दौरान, मृतक के भतीजे चंद्र देव सिंह ने 30 दिसंबर, 1958 को श्री चौधरी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने नागेश्वर सिंह पर ब्लैंक रेंज गोली चलाई थी और इस तरह उसकी हत्या कर दी गई। शपथ पर उसकी जांच करने के बाद, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने मामले को फिर से श्री एनएम चौधरी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के पास जांच के लिए भेज दिया और एक निश्चित तारीख तक रिपोर्ट करने को कहा। इस पूछताछ के दौरान,

प्रतिवादी नंबर 1 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी। -शिकायतकर्ता चंद्र देव सिंह द्वारा सात गवाह पेश किये गये और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण कराया गया। इसके अलावा, पन्नालाल साहा और शंकर घोष, जिनको याद किया जा सकता है, कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 1 के सहयोगी थे, से अदालत के गवाह के रूप में पूछताछ की गई और सुझाव यह है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने वकील के कहने पर ऐसा किया।

9 फरवरी, 1959 को, श्री एनएम चौधरी ने उप-खण्ड मजिस्ट्रेट को इस आशय की एक रिपोर्ट दी कि तीन व्यक्तियों, उपेन्द्र नियोगी, असीम मंडल और अरुण मंडल के खिलाफ धारा 302/34 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। उसी दिन, उन्होंने उप-खण्ड मजिस्ट्रेट को एक और रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। पहली रिपोर्ट के आधार पर, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया। उस रिपोर्ट में नाम दिया गया और उनके खिलाफ कमिटल कार्यवाही शुरू की गई।

दूसरी रिपोर्ट देखने के बाद उपजिलाधिकारी ने बिना कोई कारण बताए चंद्रदेव सिंह की शिकायत खारिज कर दी। चंद्र देव सिंह ने सत्र न्यायाधीश, अलीपुर के समक्ष पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन दायर किया, जिन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 को नोटिस जारी करने और उनके वकील को सुनने के बाद, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को उनके खिलाफ अग्रिम जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जो उस अदालत के एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आया। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन तीन व्यक्तियों के खिलाफ उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी करने का आदेश दिया गया था, उन्होंने भी उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया था। दोनों पुनरीक्षण आवेदनों पर एक साथ सुनवाई हुई. विद्वान न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ उपेन्द्र

नियोगी के आवेदन को भी मंजूर कर लिया। 'हमें प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने सूचित किया है कि अंततः उन तीन व्यक्तियों में से दो, जिनके खिलाफ उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी करने का आदेश दिया गया था, सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध थे, परन्तु वह निश्चित रूप से यह कहने में असमर्थ रहे कि क्या वास्तव में उन पर मुकदमा चलाया गया था और यदि हां, तो मुकदमे का नतीजा क्या निकला। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता चंद्र देव सिंह ने अनुच्छेद 134 के तहत एक आवेदन दायर किया जैसा कि पहले ही कहा गया है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा चार आधारों पर प्रमाणपत्र मांगा गया था। पहला आधार यह था कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास प्रक्रिया जारी होने से पहले आपराधिक मामले में उपस्थित होने और लड़ने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरा आधार यह था कि न्यायालय द्वारा कोई प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित परीक्षण गलत था। तीसरा आधार यह था कि एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **202** में "साक्ष्यों को सुनहरे तराजू में तौलना" का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया था। चौथा और अंतिम आधार यह था कि विद्वान उप-खण्ड मजिस्ट्रेट ने धारा 203 के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करते हुये कोई कारण दर्ज किए बिना शिकायत को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने पहले आधार को छोड़कर बाकी सभी आधारों पर सर्टिफिकेट दे दिया। इस अदालत द्वारा यह माना गया है कि -उच्च न्यायालय अपने प्रमाणपत्र को इस तरह से सीमित नहीं कर सकता है और इसलिए, हम अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी चार आधारों की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं।

पहला आधार लेते हुए, यह हमें दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVI की संपूर्ण योजना से स्पष्ट प्रतीत होता है जिसमें कहा गया है कि कोई भी आरोपी व्यक्ति प्रक्रिया

जारी होने तक सामने नहीं आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है तो उसे उपस्थित होने से रोक दिया जाता है। वह व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील या एजेंट के माध्यम से उपस्थित रह सकता है ताकि उसे पता चल सके कि क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि विचार का प्रश्न यह है कि क्या उसे किसी आरोप का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए, इसलिए उसे भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। कार्यवाही में न ही मजिस्ट्रेट के पास उसे ऐसा करने की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि जिस व्यक्ति को आरोपी के रूप में नामित किया गया है, लेकिन जिसके खिलाफ प्रक्रिया जारी नहीं की गई है, उसके कहने पर गवाहों से कोई सवाल पूछने का मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं होगा; न ही वह ऐसे व्यक्ति के कहने पर किसी गवाह से पूछताछ कर सकता है। बेशक, मजिस्ट्रेट स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा उसके सामने पेश किए गए गवाहों से ऐसे प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है जो वह न्याय के हित में उचित समझे लेकिन उससे आगे वह नहीं जा सकता। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए श्री सेठी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता के XVI अध्याय के प्रावधानों का उद्देश्य किसी आरोपी व्यक्ति को तुच्छ शिकायत से परेशान होने से रोकना है और इसलिए, जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत की जाती है, उसे परिणाम आने तक आरोपी व्यक्ति को समन जारी करने को लंबित रखने की शक्ति दी जाती है। श्री सेठी के अनुसार, इन प्रावधानों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार को आरोपी व्यक्ति द्वारा माफ किया जा सकता है और वह कार्यवाही में भाग ले सकता है। निःसंदेह, धारा 202 दप्रसं के **प्रावधानों के पीछे एक उद्देश्य है,** मजिस्ट्रेट को शिकायत में लगाए गए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करने में सक्षम बनाना है ताकि आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से तुच्छ शिकायत का सामना करने से रोका जा सके। लेकिन इस प्रावधान के पीछे एक अन्य उद्देश्य भी है और वह यह पता लगाना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में क्या

सामग्री है। जांच करते समय यह मजिस्ट्रेट का परम कर्तव्य है कि वह न केवल अनुपस्थित आरोपी व्यक्ति के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सभी तथ्यों को उजागर करे, बल्कि उस व्यक्ति या व्यक्तियों को दंडित करने की दृष्टि से भी, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत निराधार है या नहीं, यह उस स्तर पर शिकायतकर्ता द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। अभियुक्त के पास जो भी बचाव हो, उसकी जांच केवल मुकदमे में ही की जा सकती है। धारा 202 के तहत में इसे किसी भी तरह से एक मुकदमे के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून में किसी अपराध के लिए केवल एक ही मुकदमा हो सकता है। किसी आरोपी व्यक्ति को जांच के दौरान हस्तक्षेप करने की अनुमति देना इसके उद्देश्य को ही विफल कर देगा और यही कारण है कि विधायिका ने किसी आरोपी व्यक्ति को जांच में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है। यह सच है कि हमारे सामने इस मामले में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि जिन दो व्यक्तियों से अदालत के गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी, उनकी जांच प्रतिवादी नंबर 1 के कहने पर की गई थी, लेकिन तथ्य यह है कि वे ऐसे व्यक्ति थे जिन पर आरोप लगाया गया था। -पंचानन रॉय द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में प्रतिवादी नंबर 1 के सहयोगी और जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें कुछ स्थानीय लोगों ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि इस आशय का सुझाव न दिया गया हो प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित वकील द्वारा किया गया। यह निष्कर्ष अप्रतिरोध्य है और हम मानते हैं कि इस आधार पर, जांच करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच दूषित है। इस सिलसिले में, वाडीलाल पांचाल बनाम दत्तात्रय दुलाजी घडिग्सनकर (1) मामले में इस अदालत की टिप्पणियों को उपयोगी रूप से उद्धृत किया जा सकता है,

"जांच शिकायत की सच्चाई या झूठ का पता लगाने के उद्देश्य से है, यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें सबूत हैं या नहीं।" यह धारा यह नहीं कहती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है, उसके अपराध या अन्यथा का फैसला करने के लिए नियमित परीक्षण उस चरण में होना चाहिए। जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, उसे कानूनी तौर पर 'उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का जवाब देने के लिए तभी बुलाया जा सकता है जब एक प्रक्रिया जारी की गई हो और उस पर मुकदमा चलाया गया हो।''

दूसरे आधार पर आते हुए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पूरी तरह से गलत है। इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि कोई प्रक्रिया जारी की जानी है या नहीं, मजिस्ट्रेट को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि क्या "आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार" है, न कि यह कि क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है। दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है या नहीं यह केवल मुकदमे में ही निर्धारित किया जा सकता है, पूछताछ के चरण में नहीं। बार में कई निर्णयों का हवाला दिया गया जिसमें धारा 202 के तहत जांच के दायरे का सवाल उठाया गया। उन निर्णयों में से हैं: परमानंद ब्रह्मचारी बनाम सम्राट (2); राधा किशुन साव बनाम एसके मिश्रा (3); रामकिस्तो साहू बनाम बिहार राज्य (4); एम्परर बनाम जेए फिनन (5) और बैद्य नाथ सिंह बनाम मुसप्रैट (6)। इन सभी मामलों में, यह माना गया है कि धारा 202 के प्रावधानों का उद्धेश्य मजिस्ट्रेट को यह राय बनाने में सक्षम बनाता है कि प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं और उसके मन से किसी भी झिझक को दूर करना है जो शिकायत के मात्र अवलोकन और शपथ पर शिकायतकर्ता के साक्ष्य पर विचार करने पर महसूस हुई हो। अदालतों ने इन मामलों में यह भी बताया है कि मजिस्ट्रेट को यह

देखना है कि शिकायतकर्ता के आरोपों के समर्थन में सबूत हैं या नहीं, न कि दोषसिद्धि के लिए सबूत पर्याप्त हैं या नहीं। इनमें से कुछ मामलों में विद्वान न्यायाधीशों को यह देखकर कष्ट हुआ कि धारा 202 **के तहत एक जाँच की गई** की तुलना किसी परीक्षण से नहीं की जानी चाहिए जो प्रक्रिया जारी होने के बाद ही हो सकता है, और केवल एक ही परीक्षण हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि उप-खण्ड-1 धारा 202 में कहा गया है, जांच का उद्देश्य शिकायत की सच्चाई या झूठ का पता लगाना है, लेकिन जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को जांच में उसके सामने दिए गए बयानों की आंतरिक गुणवत्ता के संदर्भ में ही ऐसा करना होगा, जिसका स्वाभाविक रूप से मतलब होगा स्वयं शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए शपथ पर दिए गए बयान और शिकायतकर्ता के कहने पर परीक्षित व्यक्तियों द्वारा उसके समक्ष दिए गए बयान।

यह हमें तीसरे आधार पर लाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 जो एक मजिस्ट्रेट को शिकायत खारिज करने का अधिकार देती है, इस प्रकार है:

> "जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत की गई है या जिसे इसे स्थानांतरित किया गया है, वह शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पर दिए गए बयान (यदि कोई हो) और जांच या पूछताछ के परिणाम पर विचार करने के बाद शिकायत को खारिज कर सकता है। यदि कोई है, त धारा 202 के तहत, उसके निर्णय में आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। ऐसे मामले में वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज करेगा।"

किसी शिकायत को खारिज करने की शक्ति केवल उस मजिस्ट्रेट के पास है जिसने इसका संज्ञान लिया है। यदि प्रक्रिया जारी करने से पहले, उसने शिकायत को जांच करने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भेज दिया था, तो उसके पास

शिकायत को खारिज करने की शक्ति है, यदि उसके निर्णय में, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। हालाँकि, ऐसा करने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक शिकायतकर्ता और गवाहों द्वारा दिए गए शपथ पर दिए गए बयानों और उस जांच की जांच के परिणाम पर विचार करना है जिसे उसने एस के तहत करने का आदेश दिया था। 202 सी.आर.पी.सी. हमारे सामने आए मामले में, एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच का आदेश विद्वान उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि एक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा जांच का आदेश दिया गया था इसलिए, उन्हें इस जांच के नतीजे पर विचार करना था। इस संबंध में पंचानन रॉय द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर या शिकायत से उत्पन्न जांच के दौरान उनके सामने पेश किए गए किसी सबूत के आधार पर पुलिस द्वारा जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों पर विचार करना उनके लिए खुला नहीं था। ये सभी उनके समक्ष कार्यवाही से अप्रासंगिक मामले थे। बेशक, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज करने के लिए कोई कारण नहीं बताया है और इसलिए, हम नहीं जानते कि जब उन्होंने शिकायत को खारिज किया तो वास्तव में उनका क्या महत्व था, लेकिन उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने जो मामले को विस्तृत रूप से निपटाया है, दोनों शिकायतों में दिए गए सबूतों को अलग-अलग नहीं रखा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे मामले में गवाहों द्वारा कही गई बातों के आधार पर एक मामले के निर्णय को प्रभावित किया गया है। उच्च न्यायालय ने पन्नालाल साहा और शंकर घोष के साक्ष्यों पर भरोसा किया है जिनकी जांच जांच मजिस्ट्रेट द्वारा कभी नहीं की जानी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने पंचानन रॉय की शिकायत में पुलिस द्वारा की गई जांच पर भी भरोसा जताया है. यह सब इसके निर्णय के निम्नलिखित अंश से स्पष्ट हो जाएगा:

> "इन दो गवाहों (पन्नालाल साहा और शंकर घोष) का बयान इस तथ्य से समर्थित है कि जब पुलिस इलाके में गई तो उन्हें एक मृत पक्षी

और एक जोड़ी जूते और एक जोड़ी काली हाफ पैंट गीली हालत में मिली। यह खोज पंचानन रॉय, उपेन्द्र मंडल और तारापदो नारू द्वारा दिए गए संस्करण में मृत पक्षी और जूते की जोड़ी आदि के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। श्री अजीत कुमार दत्त ने कहा कि पूछताछ करने वाले मजिस्ट्रेट ने पन्नालाल साहा और शंकर घोष की जांच करना सही नहीं था। अभियुक्त छब्बी बोस के लिए एक वकील का सुझाव और कहा कि बाद वाले को पूछताछ में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। हालांकि, जब 'पुलिस अधीक्षक की देखरेख में अधिकारियों द्वारा मामले की पूरी जांच' पहले ही हो चुकी थी, तो यह था जांच करने वाले मजिस्ट्रेट के लिए सावधानीपूर्वक जांच करना वांछनीय और उचित है, न कि किसी इच्छुक पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों की जांच करके केवल एक तरफा जांच। इसके अलावा, इस मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट दोनों शिकायतों की एक साथ और आवश्यक रूप से जांच कर रहे थे। साक्ष्यों को समग्र रूप से देखा जा सकता है। वास्तव में, दो अलग-अलग मामले शुरू ही नहीं होने चाहिए थे, भले ही दो अलग-अलग शिकायतें दो अलग-अलग संस्करण दे रही थीं। ये शिकायतें कमोबेश पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के ख़िलाफ़ नाराजी याचिकाएँ थीं। इस दौरान सिर्फ एक घटना हुई जिसमें नागेश्वर सिंह की जान चली गयी. इसलिए दो नाराजी याचिकाओं के आधार पर दो अलग-अलग, हालांकि एक साथ जांच करने के बजाय एक ही जांच करना उचित होगा।"

जो मजिस्ट्रेट नहीं कर सका, वह करने में उच्च न्यायालय अक्षम था, और इसलिए, सत्र न्यायाधीश के आदेश को उलटने वाला उसका आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता।

हालाँकि, श्री सेठी ने वाडीलाल के मामले रिपोर्ट के 10 बिन्दु में इस अदालत के फैसले पर भरोसा जताया है। इस अदालत ने वहां इस बात पर विचार किया कि क्या कानून के मामले के रूप में, किसी मजिस्ट्रेट के लिए किसी राज्य में निजी बचाव के अधिकार की याचिका स्वीकार करना खुला नहीं था, जब उसे केवल यह निर्धारित करना था कि प्रक्रिया जारी करनी है या नहीं। विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि इस तरह की याचिका पर विचार करने के लिये एक मजिस्ट्रेट सक्षम है और कहा:

> "यदि मजिस्ट्रेट ने जांच अन्तर्गत धारा 202 के दायरे के बारे में खुद को गलत दिशा में नहीं निर्देशित किया है और अपने सामने मौजूद सामग्रियों पर न्यायिक रूप से अपना दिमाग लगाया है, तो हम सोचें कि कानून में यह मानना गलत होगा कि किसी अपवाद पर आधारित याचिका को अपने फैसले पर पहुंचने के लिए कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी याचिका का शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के मामले पर क्या प्रभाव पड़ता है, वे किस हद तक हैं अन्य गवाहों के साक्ष्यों द्वारा मिथ्याकरण, - ये सभी प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रश्नों के संबंध में कोई सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता है।"

इन टिप्पणियों के आधार पर यह आग्रह किया गया कि इस अदालत ने माना है कि एक मजिस्ट्रेट के पास जांच में दिए गए सबूतों को महत्व देने की शक्ति है। जैसा कि हम फैसले को पढ़ते हैं, यह एक अनम्य नियम नहीं बताता है, लेकिन यह मानता

है कि जांच में दिए गए सबूतों पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट इस बात पर विचार करने के लिए खुला है कि क्या आरोपी आत्मरक्षा में कार्य कर सकता था। सौभाग्य से, इस मामले में विचार के लिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन हम यह बता सकते हैं कि चूंकि धारा 202 के तहत जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि शिकायत में लगाए गए आरोप आंतरिक रूप से सत्य हैं या नहीं, मजिस्ट्रेट धारा 203 के तहत खुद को संतुष्ट करना होगा कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। वह इसके अलावा किसी भी सामग्री पर भरोसा करने का हकदार नहीं है। "अन्य गवाहों के साक्ष्य" से विद्वान न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से धारा के तहत जांच के दौरान पुलिस द्वारा जांचे गए व्यक्तियों के बयानों को ध्यान में रखा था। धारा **202** के तहत इसकी अनुमति है ।संहिता के 203 में मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के बयानों के साथ ऐसे सबूतों पर विचार करना और यह तय करना है कि प्रक्रिया जारी की जाए या शिकायत को खारिज कर दिया जाए। उस मामले की जांच पुलिस ने धारा 202 के तहत की थी। 202, सीआर. प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के कहने पर पी.सी. जाहिर तौर पर, पुलिस द्वारा पूछताछ किए गए विभिन्न गवाहों के बयान विरोधाभासी थे। ऐसा होने पर, यह प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के लिए खुला था कि वह इस पर विचार करे कि उनमें से किसे स्वीकार करना है और किसे अस्वीकार करना है। जांच करने वाले मजिस्ट्रेट ने यह नहीं कहा है और न ही उच्च न्यायालय ने हमारे समक्ष मामले में पाया है कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और उसके स्वयं के साक्ष्य आत्म-विरोधाभासी थे और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कुछ भी आंतरिक रूप से गलत था। शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमें रामगोपाल गणपतराय रुइया बनाम बॉम्बे राज्य (1) में इस अदालत के फैसले का हवाला दिया। उस मामले में, हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, वॉल्यूम से एक अंश उद्धृत

करने के बाद। 10, तीसरा संस्करण। अनुच्छेद 666 बजे पी. 365 जहां मुकदमे के लिए प्रतिबद्धता के संबंध में कानून बताया गया है, इस अदालत ने देखा है:

> "प्रत्येक मामले में; इसलिए प्रारंभिक जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि उचित स्तर के क्रेडिट के हकदार गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, और जब तक वह संतुष्ट नहीं होता है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। प्रतिबद्ध करने के लिए, उपरोक्त परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, क्या यह कहा जा सकता है कि (1) [1958] एससीआर 618,638, प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए कोई सबूत नहीं है, या कि इस मामले में पेश किए गए भारी सबूत ऐसे हैं अविश्वसनीय रूप से कि व्यक्तियों का कोई भी उचित समूह इस पर भरोसा नहीं कर सकता है? जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, इस मामले में, दस्तावेजी साक्ष्य की एक बड़ी मात्रा है - उत्तरार्द्ध पूरी तरह से किताबें और रजिस्टर और अन्य दस्तावेज हैं जो मिल्स द्वारा स्वयं रखे गए हैं या उपयोग किए जाते हैं, जो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरोपी दोषी हैं या विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उच्च न्यायालय ने यह बताने में कष्ट उठाया है कि यह उन मामलों में से एक है जहां दोनों पक्षों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। यह निर्णय जूरी को करना होगा दोनों परस्पर विरोधी संस्करणों में से किसे उनके हाथों स्वीकृति मिलेगी। यह मुख्य रूप से एक ऐसा मामला था जिसे सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंपा जाना चाहिए था, और यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि विद्वान

प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने खुद को इसके विपरीत आश्वस्त होने की अनुमति दी।''

इस प्रकार, जहां प्रथम दृष्टया मामला है, भले ही दोनों पक्षों में बहुत कुछ कहा जा सकता है, एक कमिटिंग मजिस्ट्रेट एक आरोपी को मुकदमा चलाने के लिए बाध्य है। इसलिए, बड़ा कारण यह है कि जहां प्रथम दृष्टया सबूत है, भले ही किसी आरोपी के पास वर्तमान मामले की तरह बचाव हो सकता है कि अपराध किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है, मामले को निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए उचित मंच द्वारा उचित मंच पर और प्रक्रिया जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता। संयोग से, हम बता सकते हैं कि जिस अपराध के लिए प्रतिवादी नंबर 1 पर आरोप लगाया गया है वह जूरी द्वारा विचारणीय है। उच्च न्यायालय ने जिस तरह से साक्ष्यों के साथ व्यवहार किया है, उसने वास्तव में मजिस्ट्रेट द्वारा जूरी के कार्यों को हड़पने की मंजूरी दे दी है, जिसे करने में मजिस्ट्रेट पूरी तरह से अक्षम था।

हमने ऊपर जो कहा है, उसे देखते हुए आखिरी आधार के बारे में ज्यादा कुछ कहना जरूरी नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 में प्रावधान है कि जहां मजिस्ट्रेट किसी शिकायत को खारिज कर देता है क्योंकि उसके फैसले में 'मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो उसे ऐसा करने के लिए अपने कारण दर्ज करने होंगे। यहां, जैसा कि पहले ही कहा गया है, मजिस्ट्रेट ने जांच करने वाले मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का अवलोकन किया और फिर शिकायत को खारिज करने के लिए आगे बढ़े। प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से कहा गया है कि यह उनके आदेश में मात्र एक त्रुटि है और इसलिए, इसे धारा 537ए के तहत ठीक किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में, विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1) में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया गया है। यहां गलती इस तरह की है जो मामले की जड़ तक जाती है। यह कहना संभव है कि किसी शिकायत को खारिज करने का आदेश देने के

लिए कारण बताना एक पूर्व-आवश्यकता है और कारणों की अनुपस्थिति आदेश को रद्द कर देगी।हालाँकि, यह मानते हुए भी कि स्लेनी के मामले (1) में निर्धारित नियम ऐसे मामले पर लागू होता है, पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। शिकायतकर्ता को यह जानने का अधिकार है कि पुनरीक्षण अदालत में जाने पर विचार करने के उद्देश्य से उसकी शिकायत क्यों खारिज कर दी गई है। **कारणों की अज्ञानता में रखे जाने से स्पष्ट रूप से पुनरीक्षण अदालत में जाने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जहां वह किसी मामले को पुनरीक्षण अदालत में ले जाता है,** तो उस अदालत के समक्ष उसका कार्य कठिन हो जाता है, विशेष रूप से एस के धारा 438 और 439 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के सीमित दायरे को देखते हुए। इन सभी कारणों से, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने में गलती की थी और निर्देश दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ अपीलकर्ता की शिकायत की आगे की जांच की जाए।

हालाँकि, श्री सेठी का तर्क है कि चूँकि केवल एक ही अपराध है यानी नागेश्वर सिंह की हत्या, इसलिए केवल एक ही मुकदमा हो सकता है और चूँकि उस अपराध के लिए अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, इसलिए आगे कोई पूछताछ नहीं हो सकती है।चूंकि रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए हम नहीं जान सकते थे कि उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के बाद, असीम मंडल और अरुण मंडल के खिलाफ जांच का क्या हुआ। इसलिए, हमने 24 परगना के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से एक रिपोर्ट मांगी। वह रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।उस रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि 22 मार्च, 1961 को उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबद्धता की कार्यवाही इस अदालत द्वारा वर्तमान अपील के निपटान तक रोक दी जाए।हम इस तर्क की सराहना नहीं कर सकते कि एक ही अपराध के संदर्भ में किसी भिन्न व्यक्ति के खिलाफ जांच नहीं की जा सकती।यह उस

अदालत के लिए खुला होगा जिसके समक्ष असीम मंडल और अरुण मंडल के खिलाफ प्रतिबद्धता की कार्यवाही लंबित है, यह विचार करने के लिए कि क्या उन्हें हमारे सामने प्रतिवादी के संदर्भ में जांच के परिणाम तक रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रतिवादी के खिलाफ जांच में कोई कानूनी बाधा नहीं हो सकती है।

अपील की अनुमति।

अग्रिम जांच का निर्देश दिया गया।

अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुश्री माधवी मोदी (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।